Drishti IAS

करेंट अफेयर्स बिहार

जुलाई 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार **3**

- बिहार के लिये वरदान साबित होगी गंडक-गंगा नदी जोड़ योजना 3
- पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती के तट को किया जाएगा विकसित 4
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवन पर लिखी किताब का हुआ लोकार्पण 4
- बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मिली स्वीकृति 5
- बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को मंजूरी 6
- राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में दो करोड़ से अधिक के 19 निवेश प्रस्तावों को दिया गया वित्तीय क्लीयरेंस 7
- बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि बढ़ी 7
- बिहार की बेटी बनी राष्ट्रमंडल खेल में वेटलिफ्टिंग की रेफरी 8
- अरवल और शेखपुरा बनेंगे 100 फीसदी डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले ज़िले 9
- विधानमंडल में पेश CAG रिपोर्ट : अर्थव्यवस्था को उबारने में बिहार शीर्ष 3 में 9
- क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता (सीसीसीसी) का 11वाँ संस्करण के पहले राउंड में पटना की आद्या सिंह शीर्ष पर 10
- बिहार के 5 ज़िलों को मिला 'भूमि सम्मान 2023' 11
- बिहार सरकार की ओर से राजभाषा पुरस्कार के लिये 24 साहित्यकार चयनित 12
- बिहार का विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला हुआ शुरू 13
- फिट इंडिया क्विज 2022 में केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी, पूर्व चंपारण के दो छात्र हुए सम्मानित 14
- बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिये बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एकेडमी 15
- गंगा नदी में रिवर क्रूज पर्यटन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्ल्यूएआइ) और बिहार पर्यटन विभाग के बीच समझौता 15
- बिहार सरकार ने किया कई राज्य आयोगों का पुनर्गठन 17
- बिहार की बेटी फलक की फिल्म 'चंपारण मटन'ऑस्कर की दौड़ में शामिल 18
- बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिये एडीबी और भारत सरकार द्वारा 295 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर 19
- नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को 22वाँ स्थान 20

नोट :

बिहार

बिहार के लिये वरदान साबित होगी गंडक-गंगा नदी जोड़ योजना

चर्चा में क्यों ?

29 जून, 2023 को बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शुरू होने वाली गंडक-गंगा नदी जोड़ योजना राज्य के गोपालगंज, सीवान और सारण ज़िलों के लिये वरदान साबित होगी।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना में गोपालगंज ज़िले के हीरापाकड़ के पास गंडक नदी से शुरू कर सारण ज़िले के हासिलपुर के पास गंगा नदी तक कुल 170 किमी. लंबे लिंक चैनल का निर्माण होगा। इसमें सेक्शनिंग और खुदाई के कार्य शामिल हैं।
- साथ ही, सारण तटबंध के किमी. 139.59 पर निर्धारित डिजाइन के अनुसार 4 भेंट वाले एंटी फ्लड स्लूईस का निर्माण किया जाएगा। योजना की प्राक्कलित राशि 69 करोड़ 89 लाख 79 हज़ार रुपए है।
- इस नदी जोड़ योजना से गोपालगंज ज़िले के गोपालगंज, मांझा, बरौली, सीवान ज़िले के बड़हरिया, गोरियाकोठी, महराजगंज, दरौंदा और सारण ज़िले के दिघवारा, सोनपुर, खैरा, नगरा, बनियापुर, मढ़ौरा आदि प्रखंडों के निवासी लाभान्वित होंगे।
- इन क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार और पर्यावरण संतुलन के लिहाज से भी एक महत्त्वपूर्ण योजना साबित होगी।
- विदित है कि नेपाल में हाई डैम नहीं बना है। जब तक हाई डैम नहीं बन जाता, बिहार की नदियों के पानी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेपाल में यदि हाई डैम बन जाता है तो बिहार में कोसी, कमला, बागमती, गंडक नदी के अधिकतर क्षेत्र बाढ़मुक्त हो जाएंगे।
- राज्य के पश्चिम चंपारण ज़िले में गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बरौज से निकलने वाली नहरों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाएगी। जल संसाधन विभाग इसका आकलन कर योजना तैयार करेगा। इसका उदेश्य गंडक नदी के पानी का अधिकतम उपयोग सिंचाई में किया जाना है। साथ ही, इससे गंडक नदी में हर साल आने वाली बाढ़ से भी सुरक्षा हो सकेगी।
- वर्तमान में इस बैराज से निकलने वाली नहरों से बिहार के सात ज़िलों में करीब 11.50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता है।
- ज्ञातव्य है कि वाल्मीकिनगर बैराज की अधिकतम डिस्चार्ज क्षमता करीब 8.50 लाख क्यूसेक की है, इस बैराज से 31 जुलाई, 2003 को अब तक का अधिकतम डिस्चार्ज करीब छह लाख 19 हज़ार 750 क्यूसेक हुआ था।
- इस बैराज का निर्माण 1967-68 में किया गया था। इसकी लंबाई करीब 739 मीटर है। इसका आधा हिस्सा नेपाल में है। इसमें 52 गेट, 18 रियल वे, 12 अंडर स्लूइस, 8 रिवर स्लूइस, 18 हेड रेगुलेटर गेट हैं।

नोट :

पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती के तट को किया जाएगा विकसित

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2023 को बिहार के जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि पटना में गंगा नदी के किनारे बने मरीन ड्राइव की तर्ज पर दरभंगा में भी बागमती नदी के किनारे को विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- संजय कुमार झा ने अधिकारियों से इसके आसपास के इलाकों को हरा-भरा करने की दिशा में पौधे लगाने का निर्देश दिया।
- घाट के आसपास पेड़-पौधे लगाने से लोगों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। प्रदूषण पर भी लगाम लगेगा। घाट को और अधिक समतल किया जाएगा, जिससे लोग आसानी से टहल सकेंगे।
- नदी किनारे मरीन ड्राइव की तरह पाथ-वे बनाया जाएगा। चतरिया गाँव शहरी क्षेत्र है। मरीन ड्राइव की तरह इसे अगर बना दिया जाए तो आसपास के लोगों को टहलने के लिये बेहतर विकल्प मिल जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवन पर लिखी किताब का हुआ लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2023 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी पर लिखी किताब 'नीतीश कुमार: अंतरंग दोस्तों की नज़र से' का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में इस पुस्तक की रॉयल्टी दिव्यांगों पर खर्च करने की घोषणा भी की गई।
- इस किताब के लेखक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदय कांत हैं।
- इंजीनियरिंग से पीएचडी कर चुके उदय कांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत अच्छे मित्र हैं। भागलपुर के भिखनपुर में उनका घर है। पहले वह बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य थे।
- इससे पहले उदय कांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के उप कुलपति और प्रभारी कुलपति भी रह चुके हैं।
- राजकमल प्रकाशन समूह के अध्यक्ष अशोक महेश्वरी ने कहा कि इस जीवनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक सामान्य कस्बे में रहने वाले व्यक्ति से लेकर वर्तमान मुकाम तक पहुँचने की संघर्ष भरी दास्तान है।

नोट :

बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मिली स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति के अंतर्गत बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिये प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15 प्रतिशत अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम पाँच करोड़ तक होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग की महिला, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक से पीड़ित व थर्ड जेंडर के उद्यमियों को प्लॉट एवं मशीनरी की लागत का 15.75 प्रतिशत और अधिकतम पाँच करोड़ 25 लाख रुपए दिया जाएगा।
- कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस नीति के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये इकाइयों को स्टैंड-1 क्लीयरेंस के आवेदन देने की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 है।
- साथ ही इन इकाइयों को 30 जून, 2025 तक वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिये आवेदन करना होगा।
- यह नीति संकल्प निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2028 तक प्रभावित रहेगी।
- अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बायोफ्यूल्स के उत्पादन से जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी। इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी। बायोफ्यूल्स के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और किसानों को गन्ना एवं अनाज उत्पादन का शीघ्र भुगतान प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही कचरा को कंप्रेस्ड गैस में परिवर्तित करने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे व्यापार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
- इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 के तहत आवेदन करने वाली इकाइयों के लिये आवेदन की अंतिम तिथि विस्तारित करते हुए 30 जून, 2024 कर दिया है। पूर्व में 30 जून, 2023 निर्धारित थी।

नोट :

- कैबिनेट ने इकाइयों द्वारा वित्तीय मंजूरी के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 करने की स्वीकृति दी है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 के लागू होने के बाद राज्य में कपड़े और चमड़े के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहन मिला है।
- कैबिनेट ने बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा पर नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में 25 प्रतिशत वेटेज देने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा 59 इकाइयों को पहले चरण में स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रस्तावित निवेश की राशि 311.63 करोड़ है, इस नीति के लागू होने के बाद मुजफ्फरपुर बैग कलस्टर प्रारंभ हुआ। इसमें 1100 से अधिक औद्योगिक सिलाई मशीनों पर टेक्सटाईल बैग का निर्माण किया जा रहा है।
- मुजफ्फरपुर और पटना ज़िला में भी 1000 से अधिक स्टीचिंग मशीनों के साथ टेक्सटाइल बैग बनाने की इकाइयाँ स्थापित की गई है। मुजपफरपुर में आरसीएस इंटरनेशनल व वी-2 आदि कंपनियों द्वारा वस्त्र निर्माण की इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। चमड़ा क्षेत्र में सात कंपनियों द्वारा मधुबनी में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से परियोजना लाई जा रही है।

बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार अधिनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति के तहत बिहार में काम करने वाली चिटफंड कंपनियों की जाँच और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को मिल गया है।
- राज्य की आम जनता और जमाकर्त्ताओं से अवैध जमा योजनाओं के माध्यम से धन जमा कराने पर ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिये राज्य सरकार ही सक्षम प्राधिकार बन गई है।
- कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य, सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पाबंदी नियमावली 2023 के प्रावधान में जो लोग जमा स्कीम चलाते हैं, वह इसके अधीन हो जाएंगे।
- इस नियमावली में बिहार सरकार को सक्षम प्राधिकार बनाया गया है। इससे राज्य सरकार जमा स्कीम चलानेवाली कंपनियों की जाँच करने, उनकी ऑडिट करने और अनियमितता पाए जाने के बाद कार्रवाई करने की शक्ति मिल गई है।
- राज्य सरकार को उनकी संपत्ति जब्त करने और बेचने की सभी प्रक्रिया इस नियमावली के तहत अपनायी जाएगी। राज्य में छोटे-छोटे जमा योजनाएँ चलाई जाती हैं, उनके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई होगी।
- यह नयी नियमावली आम जनता को अवैध जमा योजनाओं और धोखाधड़ी से बचाएगी। सरकार को आरोपीत के खिलाफ कड़ी सजा और भारी आर्थिक जुर्माना के साथ ही संपत्तियों की कुर्की कर निवेशकों की जमा राशि की वापसी या पुनर्भुगतान की शक्ति मिल गई है।
- विभिन्न स्तर के न्यायालयों में काम करने वाले सरकारी वकीलों का चयन अब राज्य स्तरीय चयन समिति करेगी। यह समिति महाधिवक्ता के अध्यक्षता में गठित होगी। इसमें विधि सचिव, विधि विभाग के विशेष सचिव या संयुक्त सचिव सदस्य होंगे।
- यह समिति ज़िला स्तर पर पीपी, जीपी, एपीपी एजीपी, हाइकोर्ट के लिये एडिशनल एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट एडवोकेट, प्लीडर, स्टैंडिंग काउंसिल पब्लिक प्रोस्क्युटर और सुप्रीम कोर्ट के लिये एडिशनल एडवोकेट जनरल और स्टैंडिंग काउंसिल का चयन करेगी।
- कैबिनेट में इसके लिये बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी है।
- नयी नियमावली में सरकारी वकीलों के प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर भी प्रावधान किया गया है।

नोट :

- राज्य सरकार के विधि विभाग ने बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2023 के संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
- कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कोविड 19 और यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए विदेशों से मेडिकल ग्रेजुएट करने वाले विद्यार्थियों को अब राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, ऐसे विदेश से ग्रेजुएट करनेवाले विद्यार्थियों को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के समरूप छात्रवृति भी दी जाएगी।
- विदेशों से मेडिकल ग्रेजुएट करनेवाले छात्रों को इंटर्नशिप की कुल सीटों में से 7.5 प्रतिशत सीटों पर इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा।

एनएमसी के दिशा निर्देशों के अनुसार स्टेट मेडिकल काउंसिल में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप के लिये राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा देना है। इसके लिये उन छात्रों से कोई राशि या शुल्क नहीं लिया जाएगा।

राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में दो करोड़ से अधिक के 19 निवेश प्रस्तावों को दिया गया वित्तीय क्लीयरेंस

चर्चा में क्यों ?

9 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार निवेश प्रोत्साहन परिषद ने बिहार के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में दो करोड़ से अधिक के 19 निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लीयरेंस दे दी है, जिनमें 156 करोड़ के निवेश प्रस्तावित हैं।

प्रमुख बिंदु

- निवेश करने वाली यूनिट की बैंक और सरकार की नजर में वित्तीय सुविधा और अनुदानों की पात्रता हासिल हो गई है। अब वह वित्तीय मदद लेकर प्रस्ताव के अनुरूप निवेश को धरातल पर उतार सकता है।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बिहार में कुछ नये निवेश होने जा रहे हैं, जिनमें पटना के दनियावाँ में चिप्स और स्नैक्स, भागलपुर के बरारी में जूस और सॉफ्ट ड्रिंक और गया में पोटैटो चिप्स की यूनिट लगेगी।
- सबसे अधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण और हेल्थ सेक्टर में है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को वित्तीय मंजूरी दी गई है, उनमें नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक और बेकरी के क्षेत्र हैं।
- इन जगहों पर होगा निवेश:
  - पटना ज़िले के दनियावां में चिप्स और स्नैक्स बनाने का प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसका निवेश प्रस्ताव 66.99 करोड़ रुपए का है।
  - वैशाली ज़िले के हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में नमकीन, कुरकुरे, पोटैटो चिप्स उत्पादन के लिये 38.61 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव।
  - भागलपुर बरारी औद्योगिक क्षेत्र में फ्रूट जूस और सॉफ्ट ड्रिंक के क्षेत्र में 11.13 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव।
  - पटना ज़िले में पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में स्वीट, बेकरी और नमकीन उत्पादन के लिये 10.34 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव।
  - गया ज़िले में पोटैटो चिप्स उत्पादन के लिये लगभग दस करोड़ रुपए का प्लांट स्थापित किया जाएगा।
  - बक्सर ज़िले के ब्रह्मपुर क्षेत्र में वॉयल्ड राइस के लिये 10.86 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाना है।
  - हेल्थकेयर सेक्टर में मुजफ्फरपुर के जोरन छपरा में 65 बेड के अस्पताल निर्माण के लिये 23.35 करोड़ और मधुबनी में लहरियागंज में 100 बेड के अस्पताल की स्थापना में चार करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है।
- इसके अलावा इन प्रस्तावों में जनरल मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है।

बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि बढ़ी

चर्चा में क्यों ?

9 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 13 ज़िलों में चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि का विस्तार कर दिया गया है। अब यह योजना 2025 तक चलेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि पूर्व में जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि 2022-23 तक थी।
- जैविक कॉरिडोर योजना के तहत नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन (एनपीओपी) के मानक के अनुरूप राज्य के चयनित 13 ज़िलों में कुल 20 हज़ार एकड़ को पूर्ण रूप से जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि गंगा नदी के किनारे स्थित पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार व नालंदा को जैविक कॉरिडोर बनाए गए हैं। जैविक कॉरिडोर को जल-जीवन-हरियाली का महत्त्वपूर्ण घटक बनाया गया है।
- जैविक खेती को क्लस्टर के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली प्रबंधन द्वारा मिट्टी की स्वास्थ्य व गुणवत्ता का संरक्षण, हानिकारक पदार्थों से दोषमुक्त रखा जाएगा। किसानों को आधारभूत संरचनाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
- वर्तमान में इन ज़िलों में 17507.363 एकड़ में जैविक खेती की जा रही है। बिहार राज्य जैविक मिशन इसकी मॉनीटरिंग कर रहा है।
- इस योजना के तहत खेती करने वाले किसानों को प्रथम वर्ष 11500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान के रूप में दिया जाएगा। साथ ही दूसरे व तीसरे वर्ष में 6500-6500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा।
- इस योजना के तहत कॉमन फेसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 75 फीसदी अनुदान पर आइसोलेटेट वैन, रेफ्रिजरेटेड वैन की सुविधा दी जाएगी। एजेंसी के माध्यम से जैविक उत्पादों की मार्केटिंग भी की जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
- राज्य के 38 ज़िलो में विषमुक्त अन्न का उत्पादन करने के लिये जैविक प्रोत्साहन योजना चलाई जाएगी। इसके तहत फसलों की लागत मूल्य कम उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। ऐसा होने पर किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- इस योजना के तहत किसानों को वर्मी कंपोस्ट, व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिये अनुदान मिलेगा। वर्मी कम्पोस्ट के लिये लागत का 50 फीसदी या अधिकतम पाँच हज़ार रुपए प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा।
- वहीं व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिये अधिकतम 6.40 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लाभुकों को तीन किस्तों में राशि का भुगतान किया जाएगा।

बिहार की बेटी बनी राष्ट्रमंडल खेल में वेटलिफ्टिंग की रेफरी

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सीवान ज़िले के गुठनी थाना क्षेत्र के मैरिटार गाँव की रहने वाली सृष्टि सिंह का उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका में चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि सृष्टि सिंह ने वेटलिफ्टिंग में दर्जनों पदक जीते हैं। वर्ष 2008 में आयोजित जूनियर राष्ट्रमंडल खेलों में सृष्टि सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। साल 2010 के वेटलिफ्टिंग खेल में भी सृष्टि का शानदार प्रदर्शन था।
- गौरतलब है कि 12 जुलाई को ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रमंडल सीनियर पुरुष और सीनियर महिला, जूनियर पुरुष और महिला, साथ ही महिला वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप खेल का आगाज हुआ है। यह खेल 16 जुलाई तक चलेगा। इसमें महिला, पुरुष, सीनियर, जूनियर, एवं युवा लड़के, लड़कियाँ शामिल है।

नोट :

Srishti singh, Weightlifter

अरवल और शेखपुरा बनेंगे 100 फीसदी डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले ज़िले

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जहानाबाद ज़िले के बाद अब अरवल और शेखपुरा भी 100 फीसदी डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले ज़िले बनने जा रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- अरवल में बचत खातों के लगभग 88.31 फीसदी और शेखपुरा में 92.84 फीसदी ग्राहकों को लेन-देन के लिये डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है और वे उसका उपयोग कर रहे हैं।
- अरवल ज़िले में कुल 6.78 लाख सक्रिय सेविंग खाताधारक में से 5.99 लाख खाताधारक कम-से-कम एक डिजिटल टूल का उपयोग कर रहे हैं। वहीं, 6980 चालू खाताधारक में 4397 खाताधारक यानी 62.99 फीसदी ही डिजिटल लेन-देन कर रहे हैं।
- शेखपुरा ज़िले में 5.32 लाख सेविंग खाताधरक में से 4.94 लाख यानी 92.84 फीसदी ग्राहक के पास कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद यानी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और दूसरी इसी तरह की सुविधाएँ हैं।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने देश के प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक ज़िला को सौ फीसदी डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला ज़िला बनाने का निर्णय 2019 में लिया था।
- इसके तहत बिहार में जहानाबाद ज़िला का चयन किया गया और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी हिस्सेदार (स्टेकहोल्डर) के साथ रणनीति बनाकर काम किया और जहानाबाद डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला घोषित किया गया। अब अरवल और शेखपुरा का चयन किया गया है।
- वित्तीय लेन-देन में डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैश ढोने की ज़रूरत नहीं होती है। कार्ड से पेट्रोल खरीदने पर 0 .75 फीसदी छूट, रेल टिकट, हाइवे पर टोल और बीमा खरीदने जैसे कई तरह की छूट मिलती है।

विधानमंडल में पेश CAG रिपोर्ट : अर्थव्यवस्था को उबारने में बिहार शीर्ष 3 में

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2023 को बिहार विधानमंडल में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने वाले देश के 10 शीर्ष राज्यों में बिहार तीसरे पायदान पर रहा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, बिहार ने पाँच वर्षों के दौरान उच्च स्तर पर जीएसडीपी दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय करों के हिस्से और स्वकर राजस्व में वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्ति में 30630 करोड़ रुपए यानी 23.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सामाजिक सेवाओं में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में 19727 करोड़ की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बजट प्रावधान 265396.87 करोड़ रुपए के विरुद्ध 194202.20 करोड़ रुपए यानी 73.17 फीसदी ही खर्च किया।
- अनुपूरक प्रावधान 47094.17 करोड़ रुपए पूरी तरह से बेकार हो गया, क्योंकि वह मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।
- सदन में वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2021 की स्थानीय निकायों और 31 मार्च, 2022 तक वित्तीय प्रबंधन की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें पंचायती राज संस्थान और नगर निकायों की कार्यप्रणाली और राज्य की वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाया गया है।
- सीएजी रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं ने करीब 25 हज़ार करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिये हैं। साथ ही, बजट आकार में लगातार हो रही बढ़ोतरी और उस अनुपात में राशि खर्च नहीं होने पर भी सवाल उठाया गया है।
- सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 25551 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है, हालाँकि यह घाटा विगत वर्ष की तुलना में 4276 करोड़ रुपए कम है। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य को 2004-05 के बाद तीसरी बार राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा, जो 422 करोड़ था।
- सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के बीच मिली 10952 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति दी थी, लेकिन मार्च 2022 तक के लिये समायोजन 4984 करोड़ रुपए यानी 46% तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे।
- पटना नगर निगम द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण सेवाएँ प्रदान करने के एवज में वसूले जाने वाले उपभोक्ता शुल्क वसूली में विफल होने के कारण निगम को लगभग नौ करोड़ रुपए की हानि हुई है।
- ऑडिट में यह पाया गया कि पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2007-08 से 2020-21 के बीच पंचायती राज संस्थाओं को 42940 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया था, लेकिन संस्थाओं ने 17917 करोड़ रुपए का ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिये। यह कुल राशि का 42% ही था, जबकि करीब 25000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है।

क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता (सीसीसीसी) का 11वाँ संस्करण के पहले राउंड में पटना की आद्या सिंह शीर्ष पर

चर्चा में क्यों ?

16 जुलाई, 2023 को वार्षिक अंतर-स्कूल राष्ट्रीय क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता (सीसीसीसी) के 11वें संस्करण के प्रथम राउंड की शुरुआत हुई, जिसमें नोट्रे डेम अकादमी, पटना की आद्या सिंह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- आद्या सिंह ने प्रतियोगिता की शुरुआत के 18वें मिनट में समाधान प्रस्तुत करने में काफी तेजी दिखाई और शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली की धारा मित्तल और एल. लक्ष्मीश्री, जो अभ्यास दौर में शीर्ष पर रहीं, मामूली अंतर से शीर्ष स्थान से चूक गईं और दूसरे स्थान पर रहीं। यह पहली और दूसरी रैंक के बीच एक सेकंड से भी कम का अंतर था।
- इसमें तीसरा स्थान डीपीएस, बोकारो स्टील सिटी के अनुज और आदित्य मिश्रा को मिला। इन शीर्ष 3 दावेदारों के बीच केवल 32 सेकंड का अंतर रहा।
- उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता का पहले चरण का दूसरा राउंड 23 जुलाई और तीसरा राउंड 30 जुलाई को आयोजित होगा।
- 30 जुलाई को होने वाले तीसरे राउंड के बाद लीडरबोर्ड पर संचयी स्कोर तय करेगा कि कौन सी स्कूल टीमें ऑफलाइन चरण II के लिये अर्हता प्राप्त करेंगी।
- तीन राउंड में से किसी एक में किसी राज्य या शहर में शीर्ष पर रहने वाली टीम स्वचालित रूप से अगले राउंड के लिये अर्हता प्राप्त कर लेती है।
- ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता (सीसीसीसी) 11.0 वर्ष 2013 में शुरू हुई श्रृंखला में 11वाँ संस्करण है, जो पहले प्रकाशित क्रॉसवर्ड का शताब्दी वर्ष है।
- इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा छात्रों में अन्वेषण, विश्लेषणात्मक सोच और निर्णय लेने की गुणवत्ता की भावना पैदा करना है।
- यह भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के सातवीं-बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिये खुला है। इसमें एक स्कूल टीम में दो छात्र शामिल होते हैं।

बिहार के 5 ज़िलों को मिला 'भूमि सम्मान 2023'

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये बिहार के भू-अभिलेख विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और 5 ज़िलों के कलेक्टर्स को 'भूमि सम्मान 2023' प्रदान किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने 9 राज्यों के सचिवों और 68 कलेक्टर्स को पुरस्कार दिए।
- बिहार की राज्यस्तरीय टीम और ज़िला टीम को छह क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिये सम्मानित किया गया। इनमें भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, राज्य के राजस्व मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन, अधिकार अभिलेखों का कैडस्ट्रल, मानचित्रों के साथ संबंधन, निबंधन विभाग का कंप्यूटरीकरण, निबंधन कार्यालय एवं भू अभिलेखों का एकीकरण और अंचल स्तरीय आधुनिक अभिलेखागार तैयार करना शामिल है।
- बिहार के भू-अभिलेख विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप सह सचिव जय सिंह और आइटी प्रबंधक आनंद शंकर को सम्मानित किया गया।
- इनके अलावा नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर और किशनगंज ज़िलों को भूमि सम्मान से नवाज़ा गया। इन ज़िलों के कलेक्टर्स को प्लेटिनम श्रेणी के लिये प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम केंद्र सरकार के शत-प्रतिशत वित्तपोषण से डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस द्वारा वर्ष 2008-9 से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से आधुनिक, विस्तृत और पारदर्शी भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी 2022 के बाद से अच्छा कार्य करने वाले ज़िलों को पुरस्कृत करने के लिये, उनके द्वारा कार्यक्रम के एमआईएस पर अंकित डाटा के आधार पर, मंथली ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई है। इसमें 90% से 95% तक सिल्वर, 95% से 99% तक गोल्ड और 99% से अधिक कार्य दक्षता पर प्लैटिनम ग्रेड प्रदान की जाती है।

बिहार सरकार की ओर से राजभाषा पुरस्कार के लिये 24 साहित्यकार चयनित

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 2020-21 और 2021-22 के लिये हिन्दी सेवा सम्मान से नवाजे गए 24 साहित्यकारों को आगामी 31 जुलाई को पटना के अधिवेशन भवन में सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- चयनित साहित्यकारों को पचास हज़ार से तीन लाख रुपए नकद तक की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी।
- 2020-21 के लिये चयनित साहित्यकार:
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान के लिये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का चयन किया गया है। इन्हें तीन लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

नोट :

- बीआर अंबेडकर पुरस्कार के लिये डॉ. अशोक कुमार का चयन किया गया है। इन्हें ढाई लाख रुपए नकद पुरस्कार स्वरूप दिये जाएंगे।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान मृणाल पांडेय को, बीपी मंडल पुरस्कार सुशीला टाकभरे को, नागार्जुन पुरस्कार कवि सत्यनारायण को, रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार रामश्रेष्ठ दीवान को तथा फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार प्रो. जाबिर हुसैन को दिया जाएगा। इन सभी को दो लाख रुपए नकद पुरस्कार स्वरूप दिये जाएंगे।
- महादेवी वर्मा पुरस्कार डॉ. पूनम सिंह को, बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार डॉ. के बनर्जी को, विद्याकर कवि पुरस्कार दक्षिण भारत हिन्दी प्रसार प्रचार सभा को, विद्यापति पुरस्कार गीता श्री को, मोहन लाल महतो वियोगी पुरस्कार डॉ. राकेश कुमार सिन्हा रवि को, भिखारी ठाकुर पुरस्कार भगवतीप्रसाद द्विवेदी को, डॉ. ग्रियर्सन पुरस्कार डॉ. छाया सिन्हा को तथा डॉ. फादर कामिल बुल्के पुरस्कार अनंत विजय को दी जाएगी। इन सभी को पचास हज़ार रुपए नकद पुरस्कार स्वरूप दिये जाएंगे।
- 2021-22 के लिये चयनित साहित्यकार:
- मधुसूदन आनंद को डॉ. राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान के लिये चयन किया गया है। इन्हें तीन लाख रुपए नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी।
- बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर पुरस्कार के लिये बलराम का चयन किया गया है। इन्हें ढाई लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिये जाएंगे।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार डॉ. चंद्र शिखा को, बीपी मंडल पुरस्कार डॉ. इरशाद कामिल को, नागार्जुन पुरस्कार भोला पंडित प्रणयी को, रामधारी सिंह दिनकर सम्मान अनिरुद्ध सिन्हा को तथा फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार डा. शहनाज फातमी को दिया जाएगा। इन्हें दो लाख रुपए नकद दिये जाएंगे।
- महादेवी पुरस्कार डॉ. भावना को एवं बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार डॉ. गुरमीत सिंह को दिया जाएगा। इन्हें पचास हज़ार रुपए नकद दिये जाएंगे।

बिहार का विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला हुआ शुरू

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को बिहार के नालंदा ज़िले के राजगीर में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला शुरू हो गया। 1 माह तक चलने वाले मेले के दौरान कई पवित्र स्नान होंगे। पारंपरिक ध्वजारोहण के साथ संतों और साधुओं की उपस्थिति में मेले की शुरुआत हुई।

प्रमुख बिंदु

- हिंदू धर्म में मान्यता है कि मलमास यानी अधिक मास में 33 करोड़ देवी-देवता राजगीर में प्रवास करते हैं। इस दौरान देश-प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने राजगीर पहुँचते हैं और ब्रह्मकुंड में पवित्र स्नान करते हैं।
- मलमास मेला का आयोजन तीन साल में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मलमास के दौरान राजगीर के गर्म जल कुंड में स्नान करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं।
- मान्यता है कि लगने वाले मलमास मेला के समय देश में कहीं भी पूजा-पाठ और शादी समारोह और शुभ काम नहीं होता है। मान्यता यह भी है कि मलमास मेले के ध्वजारोहण के समय मंत्र का जप करते समय पीले वस्त्र धारण किये जाते हैं, इससे लाभ प्राप्त होता है।

नोट :

फिट इंडिया क्विज 2022 में केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी, पूर्व चंपारण के दो छात्र हुए सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

23 जुलाई, 2023 को बांद्रा, मुंबई स्थित बीकेसी में केंद्रीय युवा मामले, खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिहार के पूर्व चंपारण ज़िले के केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी के स्कूल दो छात्रों को फिट इंडिया क्विज स्टेट राउंड के दूसरे एपिसोड में उनकी सफलता पर सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि अनुराग सिंह ठाकुर ने बिहार सहित 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 72 स्कूली छात्रों को फिट इंडिया क्विज स्टेट राउंड के दूसरे एपिसोड में उनकी सफलता पर सम्मानित किया।
- ये 72 छात्र अपने-अपने राज्य में टॉप स्थान हासिल करने वाले हैं और अब फिट इंडिया क्विज के राष्ट्रीय दौर में प्रतिस्पर्द्धा करेंगे, जो स्टार स्पोर्ट्स और डिज़्नी हॉटस्टार पर प्रसारित किया जाएगा।
- फिट इंडिया प्रतियोगिता 2022 में पूर्व चंपारण ज़िले के केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी के स्टूडेंट्स सम्मी जस्सी एवं हिमांशु कुमार ने स्टेट फाइनल में जीत हासिल करके ज़िले का गौरव बढ़ाया।
- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विजेता स्कूल को कुल 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली, जबकि स्कूल के 2 छात्रों की टीम को कुल 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया।
- राज्य प्रथम रनर-अप स्कूल को 1 लाख रुपए और छात्रों को कुल 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिली। इसी प्रकार स्टेट सेकेंड रनर-अप स्कूल को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिला और भाग लेने वाले छात्रों को कुल 5,000 रुपए का पुरस्कार मिला।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश दौर के लिये कुल 348 स्कूलों और 418 छात्रों का चयन किया गया था। इन छात्रों में 39% छात्राएँ थीं। चयनित स्कूलों ने दो छात्रों की एक टीम बनाई, जिन्होंने वेब राउंड की एक सीरीज के जरिये राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चैंपियनशिप के लिये प्रतिस्पर्द्धा की। 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश चैंपियनों की पहचान के लिये कुल 120 राउंड आयोजित किये गए। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश चैंपियन के रूप में पहचाने गए 36 स्कूलों में से 12 सरकारी स्कूल हैं।
- स्कूलों के लिये फिट इंडिया नेशनल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्विज का दूसरा संस्करण पिछले साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल और गृह मंत्रालय निसिथ प्रमाणिक द्वारा केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया था।
- फिट इंडिया क्विज के दूसरे संस्करण में भारत के 702 ज़िलों के 16,702 स्कूलों के 61,981 छात्रों की भारी भागीदारी देखी गई है। इसकी तुलना में फिट इंडिया क्विज के पहले संस्करण में 13,502 स्कूलों के कुल 36,299 छात्रों ने भाग लिया। पहले संस्करण की तुलना में क्विज के दूसरे संस्करण में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या में 70% की बढ़ोतरी देखने को मिली।
- गौरतलब है कि फिट इंडिया क्विज स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये खेल और फिटनेस पर भारत की सबसे बड़ी क्विज है। स्कूली बच्चों के बीच फिट इंडिया के संदेश को प्रचारित करने और स्कूलों में इसकी उपस्थिति को मज़बूत करने के उद्देश्य से 2020 में क्विज का शुभारंभ किया गया था।
- फिट इंडिया क्विज, फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसका शुभारंभ 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाना।
- क्विज में कुल 3.25 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार स्कूल और छात्रों को प्रदान किये जाते हैं। यह देश के हर कोने से छात्रों को खेल और फिटनेस में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने और राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय दौर के बाद विजेता स्कूल को कुल 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि प्रथम उपविजेता और दूसरे उपविजेता स्कूल को क्रमश: 15 लाख रुपए और 10 लाख रुपए मिलेंगे।

नोट :

बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिये बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एकेडमी

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में खेल संस्कृति विकसित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। इसके लिये राज्य में खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा, पद वर्ग स्वीकृति प्रशासकीय निकाय द्वारा इस खेल विश्वविद्यालय के लिये 31 और खेल अकादमी के लिये 81 पदों की स्वीकृति दे दी गई है।
- राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी दोनों नालंदा ज़िले के राजगीर में स्थापित होना है। यह दोनों संस्थान राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में स्थापित किये जाएंगे।
- गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान के बाद खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला बिहार छठा राज्य बन गया है। इसके लिये बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 विधानमंडल से पास किया गया था।
- इस विश्वविद्यालय के कुलपति का चयन खेल प्रशासन और खेल प्रबंधन के अनुभव के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी में से किया जाएगा। वहीं इस विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे।
- नालंदा ज़िले में बन रहे इस खेल विश्वविद्यालय में खेल से संबंधित डिप्लोमा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की योजना है। प्रारंभिक चरण में शारीरिक शिक्षा, स्पोर्ट्स फिजिक्स, खेल प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स मीडिया, खेल प्रबंधन और खेल प्रशासन संबंधी विषयों की पढ़ाई होगी।
- इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय राजगीर में होगा। राजगीर का राज्य खेल अकादमी भी इसका हिस्सा होगा। विवि से संबद्ध सभी कॉलेज में महिलाओं के लिये 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।
- खेल विश्वविद्यालय खुल जाने से बिहार में न सिर्फ खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे लोगों के लिये रोज़गार का सृजन भी होगा। इसके साथ ही राज्य में फिलहाल शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की जो कमी है, उसे भी दूर किया जा सकेगा।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश में नये फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज भी खोलने की तैयारी चल रही है, जिससे बड़ी संख्या में खेल प्रशिक्षक भी तैयार होंगे।
- विदित है कि पर्यटक नगरी राजगीर से महज पाँच किलोमीटर की दूरी पिलखी पंचायत के थेरा गांव में ठेरा हिंदुपुर मौजा के 90.765 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण हो रहा है।
- इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बन जाने के बाद यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी खेले जाएंगे। 740.82 करोड़ रुपए खर्च कर इस क्रिकेट स्टेडियम और खेल अकादमी का निर्माण किया जा रहा है।
- राजगीर में बन रहे इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सह स्पोर्ट्स एकेडमी में क्रिकेट के साथ अन्य खेलों का भी आयोजन होगा। यहाँ खेल पुस्तकालय भी होगा।
- इस स्टेडियम में इनडोर और आउटडोर खेल परिसर होगा। अकादमी में खेल का मैदान, खेल उपकरण, पुस्तकालय के साथ अनुसंधान, फिटनेस और प्रेरणा केंद्र जैसी सुविधाएँ होंगी।

गंगा नदी में रिवर क्रूज पर्यटन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्ल्यूएआइ) और बिहार पर्यटन विभाग के बीच समझौता

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में गंगा नदी में रिवर क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और बिहार पर्यटन विभाग के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुये हैं। इसके तहत 300-300 पर्यटकों की क्षमता वाले रो पैक्स वैसेल नाम के दो जलयान पटना और भागलपुर में चलेंगे।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन निदेशालय सभागार में हुए एक कार्यक्रम में इस एमओयू पर पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह की उपस्थिति में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक के. एल. रजक ने हस्ताक्षर किये।
- एमओयू के अनुसार इस जलयान (रो पैक्स वैसेल) पर पर्यटक परिभ्रमण, मांगलिक कार्यक्रमों और सामाजिक समारोह के साथ अन्य मीटिंग्स आदि के भी आयोजन किये जा सकेंगे।
- पटना में जनार्दन घाट, दीघा, पटना से कंगन घाट, पटना सिटी के बीच पहला और भागलपुर के कहलगांव, सुल्तानगंज, बटेश्वर स्थान होते हुए विक्रमशिला के डॉल्फिन सेंचुरी के बीच दूसरा जलयान संचालित होगा।
- पटना और भागलपुर में प्रत्येक 300-300 पर्यटकों की क्षमता वाले कुल दो जलयान (रो पैक्स वैसेल) का परिचालन किया जाएगा। यह जलयान करीब 15 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से पटना और भागलपुर के गंगा घाटों की सैर कराएगा।
- इस जलयान से सैर करते हुए पर्यटक कई पर्यटन स्थलों को भी देख सकेंगे। जैसे पटना के कंगन घाट से होते हुए पर्यटक श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा दर्शन के लिये जा सकेंगे। वहीं भागलपुर में पर्यटक गंगा घाटों की सैर करते हुए डॉल्फिन सेंचुरी का भी भ्रमण कर सकेंगे। दो सप्ताह के भीतर रो-पैक्स वैसेल, पटना और भागलपुर पहुँच जाएंगे।
- आईडब्ल्यूएआई के निदेशक ने बताया कि एमओयू के दो सप्ताह के भीतर पटना और भागलपुर में रो-पैक्स वैसेल पहुँच जाएंगे। इसके बाद इसका संचालन शुरू किया जा सकेगा।
- बीएसटीडीसी के प्रबंध निदेशक ने बताया कि दोनों क्रूज के संचालन के लिये निविदा की प्रक्रिया चल रही है। सभी औपचारिक प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करके पर्यटन के दृष्टिकोण से क्रूज का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

नोट :

बिहार सरकार ने किया कई राज्य आयोगों का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने कई राज्य आयोगों का पुनर्गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- बिहार राज्य महिला आयोग : पूर्व सांसद अश्वमेध देवी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं, जबकि जहानाबाद की प्रभावती मांझी, सीवान की सुजाता सुम्ब्राई, भागलपुर की रबिया खातून, गोपालगंज की सुनीता कुशवाहा, पटना के पालीगंज की श्वेता विश्वास सदस्य, पूर्णिया की सुलोचना देवी और सहरसा की प्रो. गीता यादव को राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है।
  - आयोग में समाज कल्याण विभाग, गृह विभाग और बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम एक-एक पदेन सदस्य मनोनीत किये गए हैं।
  - समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनयन तिथि से अधिकतम तीन वर्ष या 65 साल की आयु तक पूरी करने, जो पहले होगा। उस वक्त तक पद पर बने रहेंगे।
  - समस्तीपुर को दूसरी बार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पद मिला है। इससे पहले पूर्व विधायक मंजू प्रकाश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं।
  - अश्वमेध देवी कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुकी हैं। वह समता पार्टी के समय से ही पार्टी से जुड़ी हुई हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र बनने के बाद पहली बार वह सांसद बनीं। इसके बाद कई लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव लड़ीं, लेकिन हार गईं।
- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग : सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का भी पुर्नगठन किया है। विभागीय अधिसूचना के मुताबिक पूर्व विधान पार्षद रियाजुल हक उर्फ राजू को अध्यक्ष और किशनगंज के नौशाद आलम को उपाध्यक्ष बनाया गया है।
  - जहानाबाद के मुजफ्फर हुसैन राही, रोहतास के महताब आलम उर्फ काबुल अहमद, पश्चिम चंपारण के इफ्तेखार अहमद उर्फ मुन्ना त्यागी, मुजफ्फरपुर के डॉ. इकबाल समी, नवादा की अफरोज़ा खातून, सीवान के मुर्तजा अली कैसर और बेगूसराय के मुकेश जैन यानी कुल सात सदस्य भी मनोनीत किये गए हैं।
  - आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के रुप में मनोनीत पदधारकों की कार्य अवधि 25 जुलाई से अगले तीन वर्षों के लिये होगी।
- बिहार राज्य मदरसा बोर्ड : इस बोर्ड का तीन साल के लिये पुनर्गठन कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद सलीम परवेज बनाये गए हैं। कुल 13 सदस्यीय बोर्ड में पाँच पदेन सदस्य और शेष सात सदस्य बनाये गए हैं।
  - मदरसा बोर्ड के विशेष सदस्यों में विधानसभा के सदस्य महबूब आलम, सैयद रुकनुद्दीन अहमद, विधान परिषद सदस्य खालिद अनवर, मदरसा शिक्षक हूमायूँ अख्तर तारिक, मधुबनी के अब्दुल करीम अंसारी, पूर्वी चंपारण के रियाजुल अंसारी और मुजफ्फरपुर के शब्बीर अहमद शामिल हैं।
  - इसके अलावा पदेन सदस्यों में प्राच्य शिक्षा के प्रभारी शिक्षा निदेशक, निदेशक अरबी एवं फारसी स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान पटना, मदरसा इस्लामिया शमशुल होदा के प्राचार्य, बिहार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शामिल किये गए हैं।
- बिहार संस्कृत बोर्ड : इस बोर्ड का अध्यक्ष राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक भोला यादव को बनाया गया है।
  - तीन साल के लिये गठित इस बोर्ड में कुल बारह सदस्य मनोनीत किये गए हैं। इसमें दो पदेन सदस्य और नौ मनोनीत सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों में संस्कृत शिक्षा के शिक्षा निदेशक और संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।
  - नामांकित सदस्यों में विधायक विनय कुमार चौधरी, ललित नारायण मंडल, विधान पार्षद प्रेम चंद्र मिश्रा, राजद नेता और वैशाली के

नोट :

चित्तरंजन गगन, मोकामा के मदन शर्मा, मधुबनी के रामशीष यादव, विश्वविद्यालय के संस्कृत शिक्षक आचार्य सियाराम प्रसाद यादव, मधुबनी के नारायण महतो और पटना की प्रतिमा कुमारी शामिल हैं।

बिहार की बेटी फलक की फिल्म 'चंपारण मटन'ऑस्कर की दौड़ में शामिल

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की बेटी फलक अभिनीत की फिल्म 'चंपारण मटन'ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गई।

प्रमुख बिंदु

- फलक अभिनीत की फिल्म 'चंपारण मटन'ने अमेरिका, फ्राँस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों की फिल्मों के साथ अकेले स्टूडेंट अकादमी अवॉर्ड के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है।
- ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवॉर्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में फिल्म का चयन हुआ है। इस अवॉर्ड के लिये दुनियाभर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया था। 1700 से अधिक फिल्मों को चुना गया था।
- 'चंपारण मटन'फिल्म का निर्देशन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के रंजन कुमार की ओर से किया गया है। फिल्म मात्र आधे घंटे की है।
- ज्ञातव्य है कि स्टूडेंट अकादमी अवॉर्ड प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय में फिल्म बनाना, पढ़ रहे छात्र और छात्राओं को दिया जाता है, यह ऑस्कर की ही शाखा होती है। 1972 से यह अवॉर्ड अच्छी फिल्मों को दिया जा रहा है। स्टूडेंट एकेडमी अवॉर्ड चार कैटेगरी में दिया जाता है।
- 'चंपारण मटन' नैरेटिव समेत तीन अन्य श्रेणियों में शामिल है। यह एकमात्र भारतीय फिल्म है, जो इस अवॉर्ड में शामिल हुई है। विदित है कि यहाँ अवॉर्ड पाने वाली फिल्में ऑस्कर अवॉर्ड से नवाज़ी जा चुकी हैं।
- यहाँ सेमीफाइनल में इसका 16 फिल्मों से मुकाबला होने वाला है। इसी श्रेणी में अर्जेंटीना, बेल्ज़ियम, जर्मनी जैसे देश की फिल्में भी शामिल हैं।
- अभिनेत्री फलक बताती है कि आधे घंटे की यह फिल्म लोगों को अपने रिश्ते में ईमानदारी और किसी भी हाल में हार नहीं मानने के लिये प्रेरित करती है। इस फिल्म की कहानी लॉकडाउन के बाद नौकरी छूट जाने वाले शख्स पर आधारित है।
- इसकी संवेदनशीलता लोगों के दिल को छू लेती है। यही कारण है कि फिल्म को स्टूडेंट अकादमी अवॉर्ड के लिये ऑस्कर में चुना गया है।
- गौरतलब है कि भारतीय सिनेमा से लेकर हर सिनेमा के लिये ऑस्कर अवॉर्ड खास होता है। सिनेमा के जगत में इसे सबसे बड़ा अवॉर्ड माना जाता है। इसमें विजेता को कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाती है।
- इस अवॉर्ड के मिल जाने के बाद किसी भी कलाकार को पूरी दुनिया में पहचान मिल जाती है। एक अभिनेता के पूरे कॅरियर को इससे काफी फायदा पहुँचता है। अभिनेता की मार्केट वैल्यू में भी इससे काफी बढ़ोतरी हो जाती है।
- एकेडमी अवॉर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार एक ऑस्कर स्टैच्यू को बनाने में करीब 1000 डॉलर तक का खर्च होता है।
- वहीं साल 1950 तक ऑस्कर अवॉर्ड का मालिकाना हक कलाकार के पास था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन आया है। एकेडमी के नियमों के अनुसार कलाकार अब अवॉर्ड की कीमत रुपयों में नहीं लगा सकते हैं।
- अगर कोई अपने अवॉर्ड को बेचना चाहता है तो उसे एक डॉलर में अवॉर्ड ऑस्कर को वापस करना होगा। इस तरह इस अवॉर्ड की कीमत रुपयों में नहीं लगाई जा सकती है। यह अवॉर्ड पूरे देश के साथ विदेश में भी पहचान दिलाता है।

नोट :

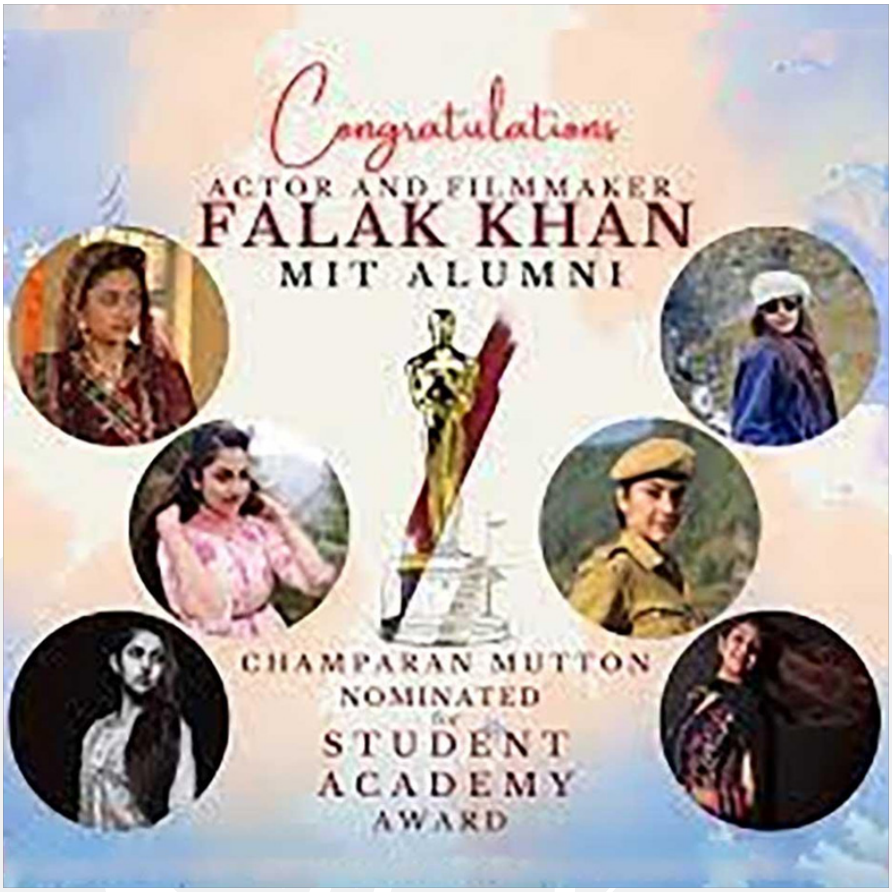

बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिये एडीबी और भारत सरकार द्वारा 295 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2023 को बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा कारकों के साथ उन्नत बनाने के लिये एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने 295 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- बिहार सड़क परियोजना में कनेक्टिविटी और स्थिरता बढ़ाने से संबंधित इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम ने और एडीबी की ओर से भारत में एडीबी के देश निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किये।
- यह परियोजना सभी राज्य राजमार्गों का मानक दो-लेन चौड़ाई में उन्नयन करने और सड़क सुरक्षा में सुधार लाने संबंधी बिहार सरकार के कार्यक्रम में सहायता करेगी। उन्नत सड़कें बिहार के कुछ सबसे गरीब ग्रामीण ज़िलों में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं और बाज़ारों तक पहुँच को बढ़ावा देंगी।
- भारत में एडीबी के देश निदेशक ताकेओ कोनिशी ने कहा कि सड़कों का उन्नयन करने के अलावा, एडीबी परियोजना राज्य सड़क एजेंसी के प्रबंधन और कार्यान्वयन क्षमता को बढ़ाने के पहले के प्रयासों पर आधारित होगी और योजना, सड़क सुरक्षा और स्थिरता के लिये प्रणालियों को मज़बूती प्रदान करेगी।

नोट :

- राज्य सड़क एजेंसी, बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को मजबूत बनाने संबंधी पहल में सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली विकसित करना शामिल होगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम की जानकारी, पुन: प्रयोज्य और टिकाऊ सामग्री सहित सामग्रियों की जाँच को सक्षम बनाने के लिये बिहार सड़क अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिये, भीड़भाड़ प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन पर अध्ययन करना और सड़क सुरक्षा उपायों में जेंडर-समावेशी प्रथाओं के लिये दिशानिर्देश बनाना सम्मिलित होगा।
- निर्माण कार्यों में महिला श्रमिकों को रोजगार प्रदान करके यह परियोजना महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी। परियोजना क्षेत्रों में समुदायों की महिलाओं को आजीविका के साथ-साथ सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के बारे में जागरूक बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि 2008 से एडीबी ने बिहार को लगभग 1,696 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के उन्नयन और गंगा नदी पर एक नए पुल के निर्माण के लिये कुल 1.63 बिलियन डॉलर के पाँच ऋण प्रदान किये हैं।

नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को 22वाँ स्थान

चर्चा में क्यों ?

- 30 जुलाई, 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का देश में ओवर ऑल 22वाँ स्थान है।

प्रमुख बिंदु

- इंडेक्स के अनुसार राज्य में सबसे अधिक निर्यात बेगूसराय ज़िला से हो रहा है। बिहार धीरे-धीरे निर्यात के हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। अभी देश के कुल निर्यात में बिहार का मात्र 0.52 फीसद ही भागीदारी है, जिसे 2025 तक बढ़ाकर 10 करने की योजना है।
- राज्य एक्सपोर्ट इंडेक्स के अन्य पैमाने पर भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। बिजनेस इकोसिस्टम में 27वाँ, निर्यात नीति के मामले में 13वाँ, निर्यात इकोसिस्टम में 25वाँ, निर्यात परफॉरमेंस में 29वाँ और लैंडलॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में बिहार का 9वाँ स्थान है।
- नीति आयोग ने इस बात का भी खुलासा किया है कि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' और 'क्लस्टर योजना' लागू होने के बाद से बिहार से निर्यात बढ़ रहा है तथा आजादी के 75 साल के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत बिहार से दुनिया के 75 देशों में निर्यात की योजना है।
- विदित है कि राज्य में निर्यात के लिये बुनियादी सुविधा अभी तक विकसित नहीं हुई है। न तो राज्य में अभी तक कोई विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड) बना है, न ही कस्टम क्लियरेंस की सुविधा निर्यातकों को उपलब्ध करवाई गई है।
- राज्य में पटना के बिहटा शहर में इनलैंड कंटेनर डिपो तो है, लेकिन वहाँ कोई विशेष सुविधा नहीं है। निर्यात के लिये पोर्ट या एयरपोर्ट तक उत्पाद पहुँचाने के लिये भाड़े में सब्सिडी तक की व्यवस्था नहीं की गई है, हालाँकि कई केंद्रीय एजेंसी राज्य के निर्यातकों को मदद करने के लिये आगे आई है।
- बिहार के हस्तशिल्प उत्पाद को बढ़ावा देने के लिये एक तरफ जहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडिक्राफ्ट (इपीसीएच) आगे आया है, वहीं सिल्क निर्यातक को मदद के लिये इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (आइएसइपीसी) तैयार है।
- केंद्रीय योजना के तहत निर्यातक को अंतर्राष्ट्रीय मेला में भाग लेने के लिये 1.25 लाख तक की मदद सरकार देगी।
- बिहार के एक दर्जन से अधिक उत्पाद ज्योग्राफिकल इंडीकेशन (जीआइ) टैग लेकर भी निर्यात नीति नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। स्थान-क्षेत्र विशेष के उत्पाद को जीआई टैगिंग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार आसानी से मिल जाता है। इससे वैश्विक पैमाने पर ग्राहकों का विश्वास मिलता है।
- गौरतलब है कि मधुबनी पेंटिंग, मुज़फ्फरपुर की शाही लीची, मखाना, सीतामढ़ी की सुजनी, सिक्की आर्ट्स, भागलपुरी सिल्क, करतनी चावल, जर्दालु आम, सिलाव का खाजा और मगही पान आदि जीआई टैग हासिल कर चुके हैं।
- जीआई टैग के बिना बिहार से गेहूँ, चावल, मक्का, बेबीकॉर्न, सब्जी, दवाएँ, चमड़े का सामान और माँस के साथ-साथ पेट्रो उत्पादों का भी निर्यात होता है।

नोट :

- ज्ञातव्य है कि राज्य से होने वाले कृषि निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार से वर्ष 2021 तक 2671 करोड़ रुपए का कृषि वस्तुओं का निर्यात किया गया है। राज्य से होने वाले निर्यात में मुज़फ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का करतनी चावल, जर्दालु आम, गेहूँ, चावल, मक्का, बेबीकॉर्न और सब्जी आदि शामिल हैं।
- बिहार के हस्तशिल्प उत्पाद की मांग दुनिया के कई देशों में हो रही है। अधिकांश वस्तुओं का निर्यात दूसरे राज्यों से होता है। अब धीरे-धीरे बिहार से भी निर्यात होने लगा है। बिहार से सालाना 36 करोड़ रुपए की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। इसे बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- आयात-निर्यात बैंक के अध्ययन आधारित सुझाव:
  - उत्पादों की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के हिसाब से हों, इसकी मॉनिटरिंग के लिये बुनियादी ढाँचा सुधारें। निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन दें, निर्यात संवर्धन अभियान चलाएँ।
  - मुज़फ्फरपुर और भागलपुर में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) स्थापित करने और पटना के मौज़ूदा आईसीडी में एक कस्टम क्लीयरेंस ऑफिस बनाएँ, निर्यात के लिये जरूरी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था दें।
  - राज्य में वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के साथ पटना, मुज़फ्फरपुर और भागलपुर में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र का विकास करें।
  - बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं के अभाव में निर्यातकों की लागत बढ़ जाती है। इसे कम करने के लिये ढुलाई-भाड़ा में सब्सिडी दें। राज्य नीति के कारण निर्यातकों का खर्च बढ़े तो रिफंड दें।
- वे उत्पाद जिनका कुल निर्यात में हिस्सा है:
  - पेट्रोलियम उत्पाद 66%
  - माँस 6%
  - चावल 10%
  - दवाएँ 3.7%
  - गेहूँ 1.3%
  - फल एवं सब्जी 1.2%
  - मशीनरीज 0.8%
  - हस्तशिल्प 1.0%

नोट :